जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 98 प्रभात अजमेर, गुरुवार 7 नवम्बर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'बुद्धिजीवियों का राजनीतिक सोच व आकलन जनता के आकलन से मेल नहीं खाता'

अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों ने बेमेल राजनीति की विडम्बना को उजागर किया

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 नवंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डॉनल्ड ट्रम्प की स्पष्ट जीत, अमेरिका की राजनीति में, चरम दक्षिणपंथी नीतियों तथा रूढ़िवाद की पुनरावृत्ति है। उदारवादी मूल्य, कट्टर दक्षिणपंथियों के स्पष्ट झूठों से भी हार गए।

डॉनल्ड ट्रम्प ने, बढ़ते इमिग्रेशन को लेकर औसत अमेरिकी नागरिक के भय का लाभ उठाया। जिसके कारण लोगों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो।

- अमेरिका के मीडिया ने ही नहीं, पाश्चात्य देशों के मीडिया ने जमकर, बिना हिचक ट्रम्प का विरोध किया था, और कमला हैरिस का समर्थन, पर जनता की भावना इससे अलग थी।
- ट्रम्प ने एक साधारण श्वेत अमेरिकी के मन में विदेशियों के भारी आगमन से जनित भय व असुरक्षा की भावना को खूब भड़काया और अन्त में भारी राजनीतिक लाभ उठाया।
- इसी प्रकार, ट्रम्प ने आम मतदाता के मन में यह भर दिया कि, अमेरिकी इकॉनमी की हालत खस्ता है। यह सच नहीं है, अमरीकी इकॉनमी 3 प्रतिशत रेट से बढ़ रही है, जो बहुप्रतिष्ठित मैगज़ीन द इकॉनमिस्ट के अनुसार ऐतिहासिक उपलब्धी है। खस्ता इकॉनमी की 'खबर' ने भी आम मध्यम वर्ग अमेरिकी के मन में बेचैनी पैदा की, जिसे भी ट्रम्प ने बखूबी, होशियारी से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काम में लिया। आम श्वेत अमेरिकी नागरिकों में व्याप्त निराशा की भावना भी ट्रम्प के लिए मददगार साबित हुई।

डॉनल्ड ट्रम्प की जीत ने अमेरिका के बुद्धिजीवियों व पत्रकारों को निरुत्तर कर दिया।

विकसित देशों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तथा ऊंची ब्याज दरों के बावजूद, जानी-मानी पत्रिका "द इकॉनमिस्ट" ने उसकी ग्रोथ को "ग्रैविटी डिफाइंग एक्सपीरिएंस" कहा था। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्षों तक अमेरिका की 3 प्रतिशत ग्रोथ रही है, जो कि अभूतपूर्व है।

तथापि, देश के आर्थिक दुःखों को दोहराने, तेल तथा कुछ खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि जैसी कमियों को बार-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिना पूर्व सूचना घर नहीं तोड़ सकती सरकार'

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने, योगी सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को तोड़ने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश को आज आड़े हाथों लिया और कहा कि रातोरात घरों को धराशायी नहीं किया जा सकता। परिवारों को घर खाली करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच, सन् 2020 के स्वतः पंज्ञान के एक केस में सुनवाई कर रही थी। इस केस का आधार मनोज टिबरेवाल आकाश नामक एक व्यक्ति का एक पत्र था। इस व्यक्ति का मकान 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका मकान, एक राजमार्ग पर कथित अतिक्रमण को लेकर, बिना कोई पूर्व सूचना दिये, ढ़हा दिया गया था।

- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के एक मामले में यू.पी. सरकार को फटकारा और कहा कि ऐसा करना गैर कानूनी है।

इस केस की सुनवाई का नम्बर, संयोगवश, ऐसे समय पर आया, जब सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य बैंच "बुलडोज़र जस्टिस" को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। ज्ञातव्य है कि "बुलडोज़र जस्टिस" शब्दावली का प्रयोग उन सम्पत्तियों को ध्वस्त कर देने के लिये किया जा रहा है, जो क्रिमिनल केसों के आरोपियों की हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के "अतिवाद" से चिंतित, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेताओं का खेमा

यह नेता गण मानते हैं, कि बार-बार अडानी के खिलाफ हर मंच से बोलने से यह छवि बन रही है कि राहुल "कॉरपोरेट जगत" व बिज़नेस के खिलाफ हैं

- रेणु मित्तल -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। राहुल गांधी किन्हीं भी मानकों के हिसाब से एक अतिवादी व्यक्ति हैं। उनके कुछ प्रिय एवं पसंदीदा विषय है, जो काफी अच्छे है, पर इसके बावजूद, इन विषयों ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाया है।

राहुल को जब-जब मौका मिलता है, वे बड़े व्यवसाय और कॉर्पोरेट भारत पर अडाणी के नियंत्रण तथा नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी नजदीकी के खिलाफ बोलते रहे हैं।

वे इन तीनों ही बिन्दुओं के इस हद तक आलोचक हैं कि उनकी छवि व्यवसाय-विरोधी तथा कॉर्पोरेट-विरोधी राजनेता की बन गई है और इससे पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है।

अपनी इस छवि को सुधारने के उद्देश्य से, राहुल ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिकों में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इस आम धारणा को ठीक करने की कोशिश की है कि वे कॉर्पोरेट या बड़े व्यवसाय के विरोधी हैं।

लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रिय विषय पर जोर देते हुये, लेख में यह तो कह ही दिया है कि किसी एक व्यक्ति (जिसे गौतम अडाणी माना जाये) को संरक्षण प्रदान करना सरकार का काम नहीं हैं।

- राहुल ने भी यह छवि सुधारने के लिए हाल ही में कुछ राष्ट्रीय व प्रादेशिक अखबारों में इंटरव्यू दिये हैं व खुद के लिखे हुए लेख छपवाये हैं, जिनमें उन्होंने कहा वे "कॉरपोरेट जगत" के खिलाफ नहीं हैं। वे केवल इस बात का विरोध कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत मोदी सरकार का ध्येय केवल एक ही औद्योगिक घराने, अडानी ग्रुप, को ही हर कीमत पर पनपाना है।
- इसी प्रकार, यह भी महसूस किया जा रहा है कि, ओ.बी.सी. जाति/जनजाति की ही बात करने से अन्य मध्य वर्ग, कांग्रेस के खिलाफ होता जा रहा है। और जैसा हरियाणा में हुआ, एस.सी. वर्ग भी कांग्रेस के विमुख हो गया। हालांकि राहुल गांधी सदा "कास्ट सैंसस" का नाम लेकर, एस.सी. वर्ग के हिमायती के रूप में उभरे हैं।

दूसरा मुद्दा, जो ऊँची जातियों के अनेकानेक कांग्रेसजनों तथा पार्टी से बाहर के लोगों को परेशान कर रहा है, यह है कि राहुल गांधी के बयान केवल ओ.बी.सी., दलितों, महिलाओं, आदिवासियों तथा ऐसे ही अन्य तबकों के बारे में आते हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना की माँग की है तथा वे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना चाहते हैं।

भाजपा सरकार इससे सहमत नहीं है लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार तथा मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी राज्य में जातिगत जनगणना करायेंगे। राहुल तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करने तथा इस बिन्दु पर चर्चा करने के लिये हैदराबाद गये थे कि राज्य में जातिगत जनगणना किस तरह के कराई जायेगी।

कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने निजी रूप से इस बात पर गहरी चिन्ता जताई है कि राहुल की यह सोच और तौर-तरीका किस तरह से ऊँची जातियों तथा मध्यम वर्ग के कांग्रेसजनों को नाराज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घड़ी चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजीत पवार के नेतृत्व वाली एन. सी. पी. (नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) को आदेश दिया कि 36 घंटे के अंदर अखबारों, जिनमें मराठी दैनिक भी शामिल हैं, में डिस्क्लेमर छपवाएं और कहे कि "घड़ी" चुनाव चिन्ह न्यायालय के विचाराधीन है।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भूयन की बैंच ने यह निर्देश दिया। अजित पवार गुट के वकील बलबीर सिंह ने कोर्ट को 36 घंटे में डिस्क्लेमर प्रकाशित होने का आश्वासन दिया।

बैंच ने पूछा था कि अखबारों में डिस्क्लेमर छपवाने के लिए आपको कितना समय चाहिए। हम आपको दिन नहीं दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटों में यह कर सकते हैं।

शुरुआत में वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने कहा था कि एन. सी. पी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन कर रही है। और पार्टी ने अखबारों से सम्पर्क किया है तथा दो-तीन दिन में डिस्क्लेमर छापने के लिए कहा है।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 36 घंटे के अंदर मराठी अखबारों सहित सभी प्रमुख अखबारों में डिस्कलेमर छापें कि घड़ी सिम्बल का इस्तेमाल अदालत में विचाराधीन है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शरद पवार गुट को भारी राहत मिली है।
- पता चला है कि अजीत गुट अपने पोस्टर्स व प्रचार वीडियो में घड़ी सिम्बल और शरद पवार के चित्रों का उपयोग कर रहा है, इस पर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

बैंच ने कहा कि, "24 घंटे में, या ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे में डिस्क्लेमर छपवाए।"

शरद पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि अजीत पवार गुट डिस्क्लेमर के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो डिलीट कर सबूत नष्ट कर रहा है।

एक नवम्बर को बारामती से लिए गए फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि अजीत पवार के पोस्टर्स में कोई डिस्क्लेमर नहीं था। अजीत पवार गुट ने हमें कोर्ट में आने को मजबूर किया है। अजीत पवार गुट द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर शरद पवार गुट ने कोर्ट में याचिका लगाई।

19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को कुछ शर्तों के साथ घड़ी का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल ने ट्रम्प को बधाई दी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। "एक्स" पर पोस्ट किये गये एक मैसेज में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में डॉनल्ड ट्रम्प की जीत के लिये उनको बधाई दी है।

मैसेज में लिखा है "डॉनल्ड

- एक्स पर अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने कमला हैरिस को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

ट्रम्प। आपकी जीत पर आपको बधाई। अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल में आपकी सफलता के लिये शुभकामनाएं।"

"कमला हैरिस को, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

'झारखंड में "शैडो एडवर्टाइज़िंग" राजनैतिक दलों के पेज से भी ज्यादा हानिकारक साबित हो रही है'

शैडो एडवर्टाइज़िंग राजनैतिक दलों से सम्बद्ध संस्थाएं कर रही हैं, जिन पर पाबंदियां लगाना मुश्किल है

- श्री नन्द झा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। चुनावाधीन राज्य झारखंड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। गुमनाम अकाउन्ट्स (शैडो अकान्ट्स) के माध्यम से किया जा रहा यह राजनैतिक खेल भाजपा द्वारा प्रेरित-प्रोत्साहित बताया जा रहा है। "टैक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट", इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल "इंडियन सिविल वॉच इन्टरनैशनल", "हिन्दूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स" तथा "दलित सॉलिडरिटी फोरम" द्वारा तैयार की गई एक संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के ये शैडो अकाउन्ट्स साम्प्रदायिक रूप से बाँटने वाले मैसेज प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। "झारखंड शैडो पॉलिटिक्स" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में चार मुख्य बाते चिन्हित की गई हैं, जिन्हें प्रचारित-प्रसारित करने की कोशिश ये शैडो अकाउन्ट्स कर रहे हैं।

- टैक जस्टिस लॉ प्रोजैक्ट, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउन्सिल, इंडियन सिविल वॉच इंटरनैशनल, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स और दलित सॉलिडैरिटी फोरम ने संयुक्त रूप से तैयार अपनी रिपोर्ट "झारखंड शैडो पॉलिटिक्स" में यह बात कही है।
- रिपोर्ट के अनुसार शैडो एडवर्टाइज़िंग के जरिए यौन हिंसा के लिए मुसलमानों को "स्टीरियोटाइप" किया जा रहा है, राजनैतिक दल यह कहते तो गैर कानूनी हो जाता।
- शैडो एडवर्टाइज़िंग के जरिए साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए "बंटेंगे तो कटेंगे" नारे का प्रचार किया जा रहा है।
- झारखंड में बाहर से आए घुसपैठियों को प्रदेश में असुरक्षा बढ़ाने का जिम्मेवार भी बताया जा रहा है।

पहला बिन्दु मुस्लिम पुरूषों की नकारात्मक रूढ़िवादिता से सम्बन्धित है। इन अकाउन्ट्स की बहुत सारी पोस्ट झारखंड में यौन-हिंसा को रेखांकित कर रही हैं तथा इन सबका दोष मुस्लिम पुरूषों तथा हेमन्त सोरेन सरकार की निष्क्रियता पर मढ़ा जा रहा है। दूसरा बिन्दु "आदिवासी मुख्यमंत्री को अमानवीयकृत छवियों" से सम्बन्धित है। इन पोस्टों में सोरेन की तस्वीरो में उनके सींग दिखाये जा रहे हैं या उन्हें कीड़े-मकोड़े के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इन छवियों के साथ प्रस्तुत मुद्रित सामग्री में, उनके काम-काज तथा नीतियों की आलोचना की गई है। रिपोर्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने ट्रम्प को जीत की बधाई दी

नयी दिल्ली, 06 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर डॉनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और उनसे भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझीदारी को मज़बूत करके वैश्विक शांति के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की है।

मोदी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, "मेरे मित्र डॉनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनाव जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ ा रहे हैं, मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझीदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं।"

- प्रधानमंत्री ने ट्रम्प से लोगों की भलाई, विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करने का आव्हान किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प की वापसी भारतीय व्यापारियों के लिए खतरे की घण्टी है?

ट्रम्प के प्रशासन में भारत में निर्मित सामान, जैसे कार, टेक्सटाइल्स व फार्मास्युटिकल्स को अमेरिका द्वारा बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी आदि का सामना करना पड़ेगा

- सुकुमार साह -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। अमेरिका ने डॉनल्ड ट्रम्प को चुनकर पुनः वाइट हाउस भेजा है। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे।

ट्रम्प की जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं। ट्रेड विशेषज्ञों एवं विश्लेषकों के अनुसार ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से भारतीय निर्यातकों को अपने सामान जैसे ऑटोमोबाइल, टैक्सटाइल और दवाओं पर भारी टैक्स का सामना करना पड़ सकता है, अगर नए प्रशासन ने "अमेरिका फर्स्ट" का एजेंडा फॉलो किया तो।

विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रम्प एच-वनबी वीज़ा नियमों को और सख्त बना सकते हैं, जिससे इंडियन आई. टी. कंपनियों की ग्रोथ व लागत प्रभावित होगी। चूंकि भारत की 80 प्रतिशत आई निर्यात आय अमेरिका से होती है। वीज़ा नीति में कोई बदलाव हुआ तो आई. टी. सैक्टर पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सालाना 190 अरब डॉलर का व्यापार होता है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी. टी. आर. आई.) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि ट्रम्प चीन के अलावा भारत व कई अन्य देशों पर भारी टैक्स लगा सकते हैं। ट्रम्प ने पूर्व में ज्यादा टैक्स के लिए भारत की कड़ी आलोचना की तथा 2020 में भारत को "टैक्स अब्यूज़र" और "टैरिफ किंग" की उपाधि दी थी। इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल भारतीय व्यापार की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा।

श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रम्प "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडा के तहत भारतीय सामानों पर भारी टैक्स लगा सकते हैं, जिससे भारतीय सामान अमेरिका में ज्यादा महंगा बिकेगा और बाजार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा।

- जैसा कि गत तीन चार साल से ट्रम्प "अमेरिका फर्स्ट" का नारा देते रहे हैं तथा भारत को टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला, टैरिफ किंग बताते रहे हैं। अतः बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी के कारण, भारतीय सामान को "कॉम्पीटिशन" का सामना करना पड़ेगा।
- इसी प्रकार ट्रम्प भारत से एच-1 बी वीज़ा पर आई.टी. इण्डस्ट्री में काम करने आने वाले भारतीय "टैकियों" के लिए अमरीका आना, रहना और महंगा और कठिन हो जायेगा और भारतीय आई.टी. इण्डस्ट्री का अमेरिका में काम करना और महंगा हो जायेगा।
- भारत के व्यापारियों के लिए केवल एक ही आशा की किरण है, ट्रम्प का "अमेरिका फर्स्ट" नारा केवल मतदाता को लुभाने के लिये, एक चुनावी जुमला ही हो और वे इसे एक राजनीतिक एजेण्डा का रूप नहीं देगें।

दूसरी ओर चीन पर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने से भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खुलेंगे भारत और अमेरिका का व्यापार 2023-24 में 120 अरब डॉलर है जो कि उससे पिछले वर्ष के 129.4 अरब डॉलर से कम है।

जी. टी. आर. आई. रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादों, फल-सब्जियों, अनाज, तिलहन आदि पर अमेरिकन टैक्स विश्व में सर्वाधिक है जिससे इनकी कीमतें 193 प्रतिशत तक बढ जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एक्सपर्ट विश्वजीत धर ने चेतावनी दी है कि ट्रम्प के राज में अमेरिका संरक्षणवादी नीति पर चलेगा खासकर इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। धर ने चिंता जताई कि ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप से ट्रम्प का अलग होना "इण्डो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसपैरिटी" के लिए संकट का संकेत हो सकता है। यह संगठन 2022 में बना था तथा 14 देश इसके सदस्य हैं।

फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के डायरैक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि ट्रम्प ज्यादा संतुलित व्यापारिक रिश्ते पर जोर देंगे, जिससे टैक्स पर विवाद हो सकता है। सहाय ने कहा कि संरक्षणवाद के प्रति रुझान में वृद्धि जारी रहेगी तथा इमिग्रेशन की नीतियां और कठोर बनेंगी।

ई. वाय. इंडिया के पार्टनर अग्नेश्वर सेन ने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे टैक्सटाइल, कैमिकल्स, दवाओं से भारतीय सामान टैक्स बढ़ाया जा सकता है। सेन ने सुझाव दिया कि भारत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर की कॉलोनी में तेंदुए से भय फैला

उदयपुर, 6 नवम्बर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लोगों का शिकार करके आतंक मचाने वाले तेंदुए ने इस बार शहर की एक कॉलोनी में अपनी उपस्थिति दर्शाकर शहर के बस्ती क्षेत्र में भय पैदा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, शहर के मल्लातलाई स्थित रामपुरा के पीपली चौक में बुधवार तड़के दो बजे एक तेंदुए ने श्वान पर हमला कर दिया। श्वान चौक में खड़ी गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था। तभी अचानक तेंदुआ वहां पहुंचा और

- बुधवार रात 2 बजे तेंदुआ चौक में खड़ी एक गाड़ी के नीचे बैठे श्वान को घसीट कर ले जाने लगा। आस-पास के अन्य श्वान इकट्ठे होकर भौंकने लगे। शोर मच जाने पर तेंदुआ भाग गया। सारी घटना सी.सी. टी.वी. में कैद हो गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)